फर्जी एनकाउंटर का खुलासा.....

पेज एक का शेष

उसका गुजरातके तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था.

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का अनुसंधान करते हुए रजनीश राय ने वर्ष 2007 में एनकाउंटर में शामिल रहे गुजरात आईपीएस तत्कालीन एटीएस डीआईजी डीजी बंजारा, एसपी राजकुमार पांडियन और राजस्थान आईपीएस दिनेश एमएन को बयान देने अहमदाबाद बुलाया था और वहीं इन्हें गिरफ्तार कर लिया था.गुजरात पुलिस में ऐसी गिरफ्तारियां और धरपकड़ पहली बार ही हुई थी. रजनीश राय ने तो इस केस के अनुसंधान में इन तीनों अधिकारियों का नारको टेस्ट करवाने तक की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई थी. नारको टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन तब से तत्कालीन बीजेपी सरकार और आईपीएस रजनीश राय में अनबन शुरू हो गई थी.

मई 2007 को रजनीश राय को मामले की जांच से हटा दिया गया. जनवरी 2010 के सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ की जांच सीबीआई को सौंपी गई. अप्रैल 2010 को सीबीआई ने डीआईजी अभय चुासमा को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद जुलाई 2010 को अमित शाह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया.रजनीश राय ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल के समक्ष बकायदा एक हलफनामा दायर कर गुजरात के पूर्व गृहराज्य मंत्री अमित शाह और डीजीपी पीसी पांडेय पर सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ के गवाह समझे जाने वाले तुलसी प्रजापति के मुठभेड़ की आपराधिक साजिश रचने और बाद में सुबूत मिटाने का आरोप लगाया.

दरअसल 2010 में गुजरात सीआईडी के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि राज्य पुलिस ने स्वीकार किया है कि सोहराबुद्दीन शेख हत्याकांड में एक प्रमुख गवाह तुलसी प्रजापति की मौत जिस मुठभेड़ में हुई, वह फर्जी थी, सीआईडी के अपराध प्रमुख वीवी राबरी ने कहा कि हमारा मानना है कि उसके (प्रजापति) साथ मुठभेड़ फर्जी थी. हमने मामले की जांच की और पाया कि इसमें कुछ पुलिस अधिकारी शामिल थे.

उसके बाद सोहराबुद्दीन मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चलती रही और अदालत के आदेश पर अमित शाह को राज्य-बदर कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर करने, सुनवाई के दौरान जज का तबादला न करने जैसे कई निर्देश दिए.

सीबीआई के विशेष जज जेटी उत्पत ने अमित शाह को मई 2014 में समन किया लेकिन अमित शाह पेश नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 26 जून 2014 को उत्पत का तबादला कर दिया गया. उसके बाद ये मामला जज लोया को सौंप दिया गया, लेकिन तब भी अमित शाह जज लोया की अदालत में भी पेश नहीं हुए. एक दिसंबर 2014 को लोया की मौत नागपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. और लोया की मृत्य के तीसवें दिन यानी 30 दिसम्बर को जज लोया की जगह नियुक्त जज एमबी गोसावी ने जांच एजेंसी के आरोपों को नामंजूर करते हुए अमित शाह को दिसंबर 2014 में आरोपमुक्त कर दिया था और उसके बाद सभी आरोपी धीरे-धीरे दोषमुक्त हो गए.

यह है असली कहानी

सीजेआई सदाशिवम जो उच्चतम न्यायालय की उस पीठ में थे, जिसने फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी को रद्द कर दिया था, उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया। इसके लिए सदाशिवम ने बाकायदा मोदी और अमित शाह को उलाहना दिया था कि उन्हें नये पद के लिए इंतजार कराया जा रहा है।

पानीपत-पलवल, एक नये रेल मार्ग का सपना दिखाया खट्टर सरकार ने

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

पलवल-असावटी-सोहना-मानेसर-गढ़ी हरसरू-फर्रुखनगर-झज्जर रोहतक-गोहाना होते हुए पानीपत जाने का ऐसा रेल मार्ग हरियाणा सरकार द्वारा चालू किये जाने की मंजूरी खट्टर जी ने दे दी है। इससे रेल यात्रियों को दिल्ली होकर नहीं जाना पड़ेगा। पानीपत से झज्जर तक व फर्रुखनगर से गढी हरसरू तक तो रेलवे लाइन मौजूद है, शेष 90 किलोमीटर रेलवे लाइन बना कर यह मार्ग पूरा करने का सब्ज़ बाग़ दिखाया जा रहा है।

पलवल से पानीपत जाने वाला शायद ही कोई ऐसा मूर्ख होगा जो इतना लम्बा चक्कर काटने में अपना समय व्यर्थ गंवायेगा, हां रास्ते की छोटी सवारियां जरूर इसका लाभ उठा सकेंगी। अव्यवहारिक एवं घाटे का सौदा लगने वाले इस मार्ग को रेलवे मंत्रालय ने तो बनाने से इन्कार कर दिया है। इस लिये खट्टर जी ने इसके लिये बाकायदा एक रेल मार्ग निगम बनाने का फ़ैसला किया है। उक्त रेल मार्ग बने या न बने लेकिन निगम में तैनात होने वाले अधिकारियों के लूट मार्ग तो जरूर बन जायेंगे।

वैसे खट्टर जी यह नहीं बताते कि यह प्रोजेक्ट कब तक बन कर चालू हो जायेगा, 2022 तक या 2069 तक? बीते दो वर्षों से केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर भी फ़रीदाबाद को गुड़गांव से मैट्रो द्वारा जोड़ने के हसीन सपने दिखा रहे हैं और उनके मंझावली पुल से तो सुधी पाठक परिचित हैं ही। समझने वाली बात तो यह है कि जिस खट्टर सरकार ने केएमपी जैसी सड़क, जिसका 60 प्रतिशत से अधिक काम खट्टर सरकार से पहले ही हो चुका था, उसे पूरा करने में चार साल लगा दिये वह रेल मार्ग कितने दशकों में बना पायेंगे? दरअसल भारतीय जुमला पार्टी को यह वहम है कि जनता केवल उनकी घोषणाओं से संतुष्ट होकर उन्हें दोबारा सत्तारुढ कर देगी, काम करने की जरूरत ही क्या है?

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

निगमायुक्त मोहम्मद शाइन के हाथ हैं काले!

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 16-22 दिसम्बर 2018 के अंक में अन्तर्राष्ट्री, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय ज्वलंत मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों-मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ की विधानसभा चुनावों में भाजपा व कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। तीनों राज्यों में भाजपा की पराजय व कांग्रेस की जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपराजेय व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कुशल रणनीतिकार व राजनीति के चाणक्य की छवि को करारा झटका लगा है, जबकि कांग्रेस का विश्वास काफ़ी हद तक लौट आया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पु के बजाए एक परिपक्व नेता के रूप में छवि उभर कर सामने आई है। इन चुनाव परिणामों से प्रतीत होता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का कांग्रेस से कड़ा मुकाबला होने की सम्भावना है। परन्तु कांग्रेस को अति उत्साह में नहीं आना चाहिये क्योंकि राजस्थान व मध्यप्रदेश में कांग्रेस व भाजपा को मिले मतों के परिप्रेक्ष्य में दोनों की स्थिति लगभग बराबर है, इसलिये लोकसभा से पूर्व कांग्रेस को जनता से किये अपने वादों को पूरा करने और कुशल शासन स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है।

'राजीव गांधी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे राहुल', 'नोटा द्वारा मतदाताओं ने बताया कि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ', तीनों राज्यों मे आम आदमी पार्टी को उतने भी वोट नहीं मिले जितने नोटा को', राहुल को साबित करना होगा कि यह बदली हुई कांग्रेस है वरना उम्मीद की कोई वजह नहीं', जनादेश ने लोकतंत्र के चौराहे पर ला खड़ा किया साहेब को', 'मोदी को राहुल गांधी से नहीं योगी आदित्यनाथ से है खतरा' तथा सॉरी मोदी सर ...देश वैसा बिल्कुल नहीं है जैसे आप हैं...' में भाजपा की पराजय और कांग्रेस की जीत के संदर्भ में विभिन्न पहलूओं से आलोचनात्मक तथ्यपूर्ण व्याख्या की गई है।

मतदाताओं की खासी अच्छी संख्या ने 'नोटा' का प्रयोग करके यह बता दिया है कि वे भाजपा व कांग्रेस दोनों में से किसी को भी अच्छा नहीं समझते तथा अनेक छोटे राजनीतिक दल भी उनके पसंद से बाहर रहे। कई राजनीतिक दलों से अधिक वोट नोटा को मिले तथा जीत-हार के अंतर से भी ज्यादा वोट नोटा को मिले। हालांकि नोटा अभी पर्याप्त नहीं है, परंतु जब नोटा वालों की संख्या पर्याप्त हो जायेगी तब सरकार व चुनाव आयोग को वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करके वास्तविक जनतंत्र का मार्ग खोजना होगा।

इस जनादेश का विश्लेषण करने से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं। पहला, मोदी-शाह का चुनाव तंत्र अजेय नहीं है। दूसरा, सत्ता द्वारा राहुल गांधी का लगातार मजाक उड़ाने और अपमानित करने के बावजूद राहुल एक परिपक्व राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं। तीसरा, राज्यों में शक्तिशाली और सक्रिय नेतृत्व का मतलब बढा है। चौथा, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिये राहुल गांधी को महागठबंधन बनाने के लिये अन्य दलों के साथ सामंजस्य बैठाने में आसानी होगी। पांचवा, मोदी के विकल्प में राहुल नज़र आते हैं तो वे अपने पिता राजीव गांधी तथा नरेन्द्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि राहुल गलतियों से सीखकर प्रधानमंत्री बनेंगे न कि अपने पिता की तरह प्रधानमंत्री बनकर गलतियां करेंगे जबकि नरेन्द्र मोदी अपनी साम्प्रदायिक, असहनशील व विभाजनकारी नीतियों के कारण एकीकृत भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते जो राहुल सहज ही कर लेंगे।

इस जीत के बाद राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रेस-कांफ्रेस में मोदीजी की अक्खड़, अहंकार व विरोधियों का मजाक उड़ाने के विपरीत शालीनता व मार्यादा को बनाए रखा तथा किसान, युवा और छोटे व्यवसायी को अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिये व 'भ्रष्टाचार' को भी एक राष्ट्रीय चिंता के रूप में चिन्हित किया, परंतु उनके राडार से श्रमिक नदारद था।

राफेल विवाद में घिरी मोदी सरकार ने अपना बचाव करने और जनता को भ्रमित करने तथा सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिये तथ्यों को तोड़ मरोड़कर गलत हलफ़नामा दिया और फैसले को अपने अनुकूल करवाया। 'राफेल में पीएसी और सीएजी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में झूठ किसने बोला?-बड़ा सवाल...चौकीदार चोर नहीं तो जांच से क्यों भाग रही है सरकार...' तथा 'गजब का एतिहासिक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने' में मोदी सरकार के झूठ तथा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कमियों की तथ्यात्मक समीक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले में इससे सम्बन्धित कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं। कीमतों पर विचार करने वाली कमेटी में बैठे तीन विशेषज्ञ अफ़सरों द्वारा बेंच मार्क कीमत को अचानक 5.2 बिलियन यूरो से बढाकर 8.2 बिलियन यूरो करने का विरोध करने पर गौर नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि कीमतों का विवरण कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) की रिपोर्ट का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) द्वारा परीक्षण किया गया था और रिपोर्ट के एक हिस्से को संसद में पेश किया गया था, जबकि सीएजी रिपोर्ट अभी तक फाइनल ही नहीं हुई है। डसाल्ट की 2012 में जिस रिलायंस कंपनी से बातचीत चल रही थी वह मुकेश अंबानी की कम्पनी थी न कि अनिल अंबानी की जबकि यह तो 2015 में बनी थी। कोर्ट ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वाओलांद का बयान कि राफेल करार में भारतीय कंपनी का चयन नई दिल्ली के इशारे पर किया गया था पर भी कोई टिप्पणी नहीं की। इस करार से दो दिन पहले अर्थात 8 अप्रैल 2015 तक विदेश सचिव कहते रहे कि हिंदुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इस करार में शामिल है, फ़िर एचएएल को डील से बाहर क्यों किया गया? कांग्रेस इन सवालों के जवाब के लिये जेपीसी की मांग के साथ मैदान में डटी हुई है, जबकि मोदी सरकार सवालों का जवाब देने की बजाए कोर्ट के इस विवादित फैसले को अपनी जीत बताकर आक्रामक हो रही है। परंतु यह विवादित फैसला किसी भी रूप में सरकार को किसी तरह का क्लीन चिट नहीं है।

हरियाणा की राजनीति में जाट बेल्ट शुरू से हावी रही है परंतु गत विधान सभा चुनाव में भाजपा की सत्ता स्थापित होने के बाद से जाट बेल्ट अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। जाट मतदाता महसूस करने लगे हैं कि भाजपा की जाट नेता उनकी आशाओं पर खड़े नहीं उतरे। चौटाला खानदान की आपसी लड़ाई के कारण इंडियन नेशनल लोक दल विभाजन का शिकार हो रहा है। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े पुत्र अजय के बेटों दुष्यंत व दिग्विजय ने अपने चाचा अभय चौटाला को चुनौती देते हुए जन नायक जनता पार्टी खड़ी कर ली है। 'दुष्यंत साफ़-साफ़ बताओ, क्या तुम भाजपा से समझौता करोगे-हरियाणा की जाट बेल्ट हिन्दूवादी पार्टी को उखाड़ने के लिये तैयार बशर्ते...' में आगामी विधानसभा के मद्देनज़र भाजपा के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्भावित समीकरण का मूल्यांकन किया गया है।

आस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप की कोयला परियोजना को शुरू करने के लिये कहीं से भी आर्थिक मदद व आवश्यक स्वीकृतियां नहीं मिलने के बावजूद अडानी ग्रुप द्वारा काम शुरू करने के एलान से वहां की जनता व प्रशासन हैरान है और युवा व छात्र इसका विरोध कर रहे है। क्वीन्सलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ़ एनवायरनमैंट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिना स्वीकृति का खनन स्थल पर कोई प्रभावी काम नहीं किया जा सकता, जिसका 'आस्ट्रेलिया में अडानी की कोयला परियोजना के खिलाफ़ सड़कों पर उतरे हज़ारों छात्र-युवा' में विवेचन किया गया है। अडानी को अहसास हो जाना चाहिये कि वहां भारत की मोदी सरकार की तरह उसे संरक्षण देने वाला कोई नहीं है।

'डॉक्टर को भगवान मानने का चलन कहां चला गया-राम नहीं रहे, आप भी अब राम भरोसे न रहिये...' तथा 'मेडिकल शिक्षा का ढांचा ही लूट की प्रेरणा देता है' के जरिये मेडिकल कॉलेजों द्वारा ली जा रही भारी फ़ीस और निजी चिकित्सा संस्थानों में हर चिकित्सक का टार्गेट सेट करने और वेतन कम देने से चिकित्सा क्षेत्र में जारी अव्यवस्था और बदहाली को उजागर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'आयुष्मान भारत' का ढिंढोरा पीटने के बजाए चिकित्सा क्षेत्र के पूरे ढांचे को ही व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

'निगमायुक्त मोहम्मद शाइन के हाथ हैं काले! ठेकेदार से कमीशन लेकर बंद खाते का चैक दिया, तबादले पर 30 फ़ाइलें चुरा ले गये' में कमिश्नर शाइन के कारनामों का काला चिट्ठा खोला गया है जो ईमानदार मुख्यमंत्री खट्टर के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे पर करारी चोट है। विडम्बना है कि शाइन को विजिलेंस जांच की भी कोई परवाह नहीं है। वैसे तो नगर निगम भ्रष्टाचार, अनियमितताओं व घोटालों का अड्डा बना हुआ है जिसका खामियाजा जनता व निगम के खजाने को भुगतना पड़ रहा है।

'कहो नरेन्द्र-मोदी की चुप्पी' कविता के माध्यम से मोदी सरकार के कारण इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने व डॉलर के मुकाबले रुपया धराशायी होने तथा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनारस को क्योटा बनाने का दावा करने और गंगा मैया की जय जयकार करने व हर माह मन की बात करने, परंतु किसान की बदहाली, गंगा के लये अग्रवाल द्वारा जान गंवाने तथा देश की असलियत को नज़र-अंदाज करते हुए नीरो द्वारा चैन की बंशी बजाने की तरह मोदीजी द्वारा लगातार अपनी पीठ थपथपाने पर उचित व्यंग्य किया गया है।

संघ परिवार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पत्नी छोड़ देने पर त्यागी और अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहने पर 'बीबी छोड़ देने से कोई गौतम बुद्ध और टकला होने से कोई चाणक्य नहीं हो जाता', गाय का दूध निकालने वाले को गाय की लात लगने पर, राजस्थान -मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ में राहुल गांधी द्वारा मोदी-शाह को पटकनी देने पर 'मैने बोला था न, 'इंदिरा जी का पोता है, घर में घुसकर मारेगा' तथा प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लूट पर 'आइसीयू-नहीं, कार्टूनों द्वारा उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।